संख्या-158/2018/2748/41-2018-13(बजट)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

विषय- जनपद गोरखपुर स्थित शहीद स्मारक चौरी-चौरा के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1395/6-1-1(947)/2018, दिनांक 31 मई, 2018 एवं पत्र सं0-2966/6-1-1/2018, दिनांक 10 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर शहीद स्मारक चौरी-चौरा के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस) द्वारा लोक निर्माण विभाग से विधीक्षित कराकर उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष रू०2,17,65,000.00 (रूपये दो करोड़ सत्रह लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू०1,08,83,000.00 (रूपये एक करोड़ आठ लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों/शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी। प्रायोजना का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग में संचालित योजनाओं /परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों/आगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन (अप्रेजल) हेतु गठित समिति की दिनांक 12 जुलाई, 2018 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग के पत्र सं0- 2306/41-2018-80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0ओ0/2017, दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना में कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन में मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं इसके अनुश्रवण का दायित्व महानिदेशक पर्यटन कार्यालय एवं क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी का होगा।

(5) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि वृद्धि/कमी होती है तो इस स्थिति में प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिदेशक पर्यटन द्वारा शीघ्र सक्षम स्तर का पुन: अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, पर्यटन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हुआ है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित है अथवा किया जाना प्रस्तावित है।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत एवं अनुमन्य सेन्टेज के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्यरूप से प्राप्त की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति सहित विस्तृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आगणन (डी0पी0आर0) की एक प्रति कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए पर्ट चार्ट सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यों की मदों में ही किया जायेगा। यदि परियोजना के स्वीकृत कार्यों में कोई परिवर्तन होता है तो शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) प्रायोजना के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को जी0एस0टी0 वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार देय होगी तथा प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जी0एस0टी0 के वास्तविक भुगतान की सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तभी प्रायोजना की द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(15) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी एवं महानिदेशक, पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी एवं पर्यटन निदेशालय का होगा।

(16) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में दिव्यांगजनों की सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त सोशल आडिट से सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत परियोजना के लिए प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-39-जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य कार्य के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-881/दस-2018 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-158/2018/2748(1)/41-2018-13(बजट)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), लखनऊ ।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), निर्माण प्रखण्ड गोरखपुर प्रथम ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
10- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, गोरखपुर ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।